



1 June, 2023

## पुराना किला उत्खनन दिल्ली के इतिहास को मौर्य काल से संबंधों को उजागर करता है

**प्रसंग:** हाल ही में पुराना किला की खुदाई में मौर्य युग की कलाकृतियाँ मिली हैं  
उत्खनन के मुख्य बिंदु

- दिल्ली के पुराना किला (पुराना किला) में खुदाई से मौर्य काल से पहले के शहर के निरंतर इतिहास का पता चला है।
- 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के चित्रित ग्रे वेयर (PGW) मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए गए हैं।
- पुराना किला को महाभारत में वर्णित इंद्रप्रस्थ का स्थल माना जाता है।
- विभिन्न ऐतिहासिक काल से विभिन्न कलाकृतियों को उजागर किया गया है, जिसमें 900 वर्षीय वैकुण्ठ विष्णु, देवी गज लक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका, 2,500 साल पुरानी टेराकोटा की अंगूठी, और सुंग-कुषाण काल से चार कमरे का परिसर शामिल है।
- सिक्के, मुहरें, मोहरें, तांबे के सिक्के और एक हड्डी की सुई मिली है, जो एक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी भूमिका का संकेत देती है।
- जनवरी 2023 में शुरू की गई खुदाई का उद्देश्य साइट की पूरी कालक्रम स्थापित करना है, प्रारंभिक कुषाण स्तर से 5.50 मीटर की गहराई पर संरचनाओं का खुलासा किया जा रहा है।
- पिछली खुदाई 2013-14, 2017-18, 1954 और 1969-73 में की गई थी।
- वर्तमान उत्खनन के निष्कर्ष प्राचीन शहर इंद्रप्रस्थ के बारे में और जानकारी प्रदान करेंगे।
- बरामद कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए पुराना किला में एक ओपन-एयर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें हिंदू देवी-देवताओं, सिक्कों और मुहरों की मूर्तियाँ शामिल हैं।
- साइट के ऐतिहासिक महत्व और कलाकृतियों से जी-20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों सहित आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।

### पुराना किला:

- पुराना किला, 16वीं शताब्दी में अफगान शासक शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था।
- पुराना किला का निर्माण 1538 ईस्वी में शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और मुगल सम्राट हुमायूँ द्वारा पूरा किया गया।
- किला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि माना जाता है कि यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित पांडवों की पौराणिक राजधानी इंद्रप्रस्थ के स्थल पर स्थित है।
- पुराना किला मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस टिकाऊ और दिखने में आकर्षक सामग्री का उपयोग करके किले की दीवारों, प्रवेश द्वारों और गढ़ों का निर्माण किया जाता है।
- आज, पुराना किला एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खड़ा है, जो आगंतुकों को अपनी प्रभावशाली वास्तुकला, शांत परिवेश और दिल्ली के प्राचीन अतीत की आकर्षक झलक के साथ आकर्षित करता है।



## यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO)

**प्रसंग:** पहलवानों के विरोध के पेचीदा मामले ने POCSO अधिनियम को समाचारों में ला दिया है।

**अधिनियम की विशेषताएं:**

- 2012 का POSCO अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 22 मई, 2012 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, और 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ।
- यह अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से बचाने, यौन शोषण के विभिन्न रूपों को परिभाषित करने और अपराधियों के लिए कठोर दंड स्थापित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को वर्गीकृत करता है, जिसमें पेनिट्रेटिव यौन हमला, गैर-प्रवेशात्मक हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करता है ताकि कानूनी कार्यवाही के दौरान बाल पीड़ितों द्वारा अनुभव किए गए आघात को कम किया जा सके और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
- POSCO अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले अपराधियों को कठोर कारावास सहित कारावास से लेकर जुर्माने तक की सजा हो सकती है। गंभीर अपराधों के मामलों में जिसके परिणामस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो जाती है, अधिनियम में मृत्युदंड का प्रावधान है।
- अधिनियम के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, यह प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना, बाल कल्याण समितियों की नियुक्ति और जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बाल-सुलभ प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने का आदेश देता है।
- POSCO अधिनियम भी सरकार को जन जागरूकता अभियान चलाने, बाल अधिकारों और सुरक्षा पर शिक्षा और संवेदीकरण कार्यक्रम प्रदान करने और बाल-सुलभ तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम और जागरूकता के महत्व पर जोर देता है।

## Face to Face Centres





1 June, 2023

➤ यह अधिनियम बाल यौन शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस मुद्दे को हल करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने में सहायक रहा है। यह भारत में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है।

जब बच्चे के अधिकारों की बात आती है, तो एक और निकाय जो दिमाग में आता है वह है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)।

### राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR):

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- अधिनियम के तहत, एक बच्चे को 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरूप हों।
- संरचना : इस आयोग में अध्यक्ष और छह सदस्य हैं जिनमें से कम से कम दो महिलाएँ होनी चाहिए।
  - इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए की जाती है।
  - आयोग में सेवा करने के लिए अधिकतम आयु अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है।
- अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

### सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) प्रोजेक्ट 2.0

प्रसंग: केंद्र सरकार ने CITIIS परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।

#### मुख्य विशेषताएं:

- स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत CITIIS (सिटी इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन) परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
- परियोजना का उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है।
- सिटीज 2.0 को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 18 शहरों में लागू किया जाएगा।
- यह एक चार साल की परियोजना (2023-2027) है जिसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), यूरोपीय संघ (EU), और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान (NIUA) के साथ साझेदारी में लागू किया गया है।
- फंडिंग में AFD और KfW से ₹1,760 करोड़ का ऋण, समान रूप से विभाजित, और यूरोपीय संघ से ₹106 करोड़ का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल है।
- केंद्र, राज्य और शहर के स्तर पर जलवायु शासन के हस्तक्षेप को लागू करने और जलवायु अनुकूलन और शमन उपायों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

#### CITIIS परियोजना (चरण 1 या 1.0)

- जुलाई 2018 में एजेंस के साथ साझेदारी में CITIIS (सिटीज इनवेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन) नामक एक अखिल भारतीय चुनौती शुरू की गई थी। फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (AFD) और यूरोपीय संघ।
- एजेंस द्वारा 100 मिलियन यूरो का ऋण दिया जाएगा Française de Développement (AFD), जिसे अखिल भारतीय चुनौती के माध्यम से चयनित 15 नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट शहरों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- परियोजनाएं चार क्षेत्रों में थीं - टिकाऊ गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, शहरी प्रशासन और आईसीटी और कम आय वाले बस्तियों में सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार।

#### KEY VALUES

- Excellence in sustainable urban development
- Innovation and integration
- Participatory approaches
- Relevance and feasibility

## NEWS IN BETWEEN THE LINES

### राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

संदर्भ: एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी के रुझान प्रकाशित किए हैं

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो सांख्यिकीय डेटा के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के दायरे में कार्य करता है।
- इसका गठन 2019 में सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक एकीकृत इकाई बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) को मिलाकर किया गया था।
- NSO कृषि, उद्योग, सेवाओं और सामाजिक संकेतकों सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सटीक और विश्वसनीय सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसके कार्यों में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण और जनगणना करना, राष्ट्रीय आय खातों को संकलित करना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का अनुमान लगाना और प्रमुख आर्थिक संकेतकों की निगरानी करना शामिल है।

### Face to Face Centres





	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NSO के डेटा और रिपोर्ट का उपयोग नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों और आम जनता द्वारा सूचित निर्णय लेने, आर्थिक रुझानों की निगरानी करने और साक्ष्य-आधारित नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाता है।</li> </ul>
<p><b>सावित्रीबाई फुले: आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका</b></p>	<p><b>प्रसंग:</b> सावित्रीबाई फुले पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए इंडिक टेलस नाम की एक वेबसाइट पर जांच शुरू की गई है</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को नायगांव, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था।</li> <li>➤ उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ 1848 में पुणे, महाराष्ट्र में पहले लड़कियों के स्कूल की सह-स्थापना की। स्कूल का नाम " भिडेवाडा " रखा गया।</li> <li>➤ सावित्रीबाई फुले ने गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए एक देखभाल केंद्र और विधवाओं के लिए "महिला सेवा मंडल " नामक एक घर भी स्थापित किया।</li> <li>➤ महिलाओं की शिक्षा और भारतीय समाज में सामाजिक असमानताओं के खिलाफ लड़ाई पर स्थायी प्रभाव पड़ा है।</li> <li>➤ सावित्रीबाई फुले ने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी, जो उत्पीड़ित और हाशिए के समुदायों के उत्थान की दिशा में काम कर रही थी।</li> </ul>
<p><b>चोलिमा 1 (Chollima-1)</b></p>	<p><b>प्रसंग:</b> उत्तर कोरिया का अपना पहला जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का प्रयास विफल हो गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इस विफलता को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच नेता किम जोंग-उन की सैन्य क्षमता बढ़ाने की कोशिशों को झटके के रूप में देखा जा रहा है।</li> <li>➤ रॉकेट का नाम <b>चोलिमा-1</b> रखा गया था और जिस जासूसी उपग्रह को तैनात किया जाना था उसका नाम <b>मालीगयोंग-1</b> था।</li> <li>➤ उत्तर कोरिया ने जल्दी ही विफलता को स्वीकार कर लिया और विफलता के कारणों की जांच के बाद दूसरा प्रक्षेपण करने का वचन दिया।</li> <li>➤ लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने संक्षेप में निवासियों को आश्रय सलाह जारी की।</li> <li>➤ एक उपग्रह का प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करता है जो उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक तकनीक पर आधारित किसी भी प्रक्षेपण का संचालन करने से रोकता है।</li> </ul>
<p><b>ग्राफीन</b></p>	<p><b>ग्राफीन की विशेषताएं :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ग्राफीन कार्बन का एक द्वि-आयामी आवंटन है, जिसमें हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। यह केवल एक परमाणु की मोटाई के साथ ज्ञात सबसे पतली सामग्री है।</li> <li>➤ ग्राफीन बिजली और गर्मी दोनों के लिए दुनिया का सबसे पतला, मजबूत और सबसे सुचालक पदार्थ है।</li> <li>➤ यह तांबे से बेहतर बिजली का संचालन करता है और छह गुना हल्का होने के साथ ही स्टील से <b>200 गुना मजबूत</b> है।</li> <li>➤ ग्राफीन लगभग पारदर्शी है, केवल <b>2%</b> प्रकाश को अवशोषित करता है, और हाइड्रोजन और हीलियम सहित गैसों के लिए अभेद्य है।</li> </ul> <p><b>अनुप्रयोग:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बिजली, चालकता, ऊर्जा उत्पादन, बैटरी, सेंसर, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, खेल उपकरण, निर्माण आदि सहित विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है।</li> <li>➤ ग्राफीन-आधारित सामग्री का उपयोग उच्च प्रदर्शन वाली बैटरी, सुपरकैपेसिटर, टचस्क्रीन, प्रवाहकीय स्याही, सेंसर, जल शोधन, विलवणीकरण और यहां तक कि COVID-19 महामारी के दौरान ग्राफीन-आधारित मास्क में भी किया गया है।</li> <li>➤ रक्षा और एयरोस्पेस में, ग्राफीन की असाधारण ताकत इसे कवच, बैलिस्टिक सुरक्षा, स्टीलथ कोटिंग्स और रडार सिग्नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप को कम करने वाली सामग्री के लिए एक आशाजनक सामग्री बनाती है।</li> <li>➤ पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति ग्राफीन की संवेदनशीलता इसे रासायनिक और जैविक एजेंटों, विस्फोटकों, विकिरण और अन्य खतरनाक पदार्थों के संवेदन के लिए उपयुक्त बनाती है।</li> <li>➤ वैश्विक ग्राफीन बाजार का आकार <b>\$175.9</b> मिलियन था और 2023 और 2030 के बीच <b>46.6%</b> की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।</li> <li>➤ चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और सिंगापुर ग्राफीन अनुसंधान में अग्रणी देश हैं, चीन ग्राफीन से संबंधित पेटेंट फाइलिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी है।</li> <li>➤ ग्राफीन का वाणिज्यिक उत्पादन चीन और ब्राजील द्वारा किया जाता है, जबकि भारत चीन का <b>1/20</b> उत्पादन करता है, जो उनकी तुलना में बहुत कम मात्रा में है।</li> </ul>







1 June, 2023

## शेयर बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्ग

**संदर्भ :** सरकार ने OFS मार्ग के माध्यम से कोल इंडिया में 3% तक हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।

- ऑफर फॉर सेल (OFS) भारत के प्रतिभूति नियामक SEBI द्वारा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को बेचने के लिए 2012 में शुरू की गई एक विधि है।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों को उनकी होल्डिंग कम करने और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बढ़ावा देना है।
- SEBI के नियमों का पालन करने के साधन के रूप में OFS निजी और राज्य के स्वामित्व वाली दोनों सूचीबद्ध कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो गया।
- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपने शेयर बेचने के लिए OFS रूट का भी इस्तेमाल किया।
- OFS शेयरों को बेचने का एक आसान और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है, जिससे भारतीय शेयर बाजार में कंपनियों और निवेशकों दोनों को लाभ होता है।
- सेबी के अनुसार, OFS में:
- 5% संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों आदि द्वारा आरक्षित होना चाहिए।
- खुदरा निवेशकों के पास 10% होना चाहिए।

## लेबनान

**प्रसंग:** लेबनान के सीरिया नियंत्रित क्षेत्र में एक विस्फोट में 5 फिलिस्तीनी आतंकवादी मारे गए।

**राजधानी:** बेरूत

**पड़ोसी देश और जल निकाय:**

- उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल।
- पश्चिम में भूमध्य सागर।

**क्षेत्र में संघर्ष:** लेबनान के पूर्वी क्षेत्र पर फिलिस्तीन-समर्थक सीरियाई लोगों का कब्जा है और दक्षिणी लेबनान इजरायल सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोनों क्षेत्रों के बीच संघर्ष ने देश को परेशान रखा है।



## समाचार में स्थान

## ओकिनावा द्वीप

**संदर्भ :** ओकिनावा द्वीप कि ओर बढ़ते हुए टायफून मावर अब कमजोर पड़ रहा है।

**देश:** जापान (ओकिनावा प्रान्त)

**महत्व:** संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वीपों के समूह पर एक सैन्य उपस्थिति है। अमेरिकी सेना गैरीसन यहां सेवाओं और कार्यक्रमों के केंद्र के रूप में टोरी स्टेशन और गैरीसन के लिए आधिकारिक मुख्यालय के रूप में नौ प्रतिष्ठानों और पांच दूरस्थ साइटों को सहायता प्रदान करता है।



## Face to Face Centres

